हूं कि अगर आवश्यक हो तो कानून में बदलाव करके दलित मुसलमानों और ईसाइयों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। धन्यवाद।

Demand to bring out the Sachar Committee Report in Urdu

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, the Prime Minister's High Level Committee headed by Justice Rajendra Sachar prepared a report on the social, economic and educational status of the Muslim community. The Report of the Sachar Committee was placed before the august House in English; it is also available on the website of the Committee. The Committee also informed that out of the 14.3 per cent Muslims of the country, a sizeable number are Urdu-speaking.

Sir, I would urge upon the Government to bring out the aforesaid report in Urdu language for the large number of Urdu-speaking people of the country.

Demand to give Priority to Bihar for Development of the State

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) **:** महोदय, बिहार एक पिछड़ा राज्य हैं। यह राज्य हर दृष्टि से पीछे है। चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, हर मामले में बिहार की स्थिति काफी खराब हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो इस राज्य मे पड़ते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं हैं। जगह-जगह सड़कें टूट गई हैं और उनमें गढ्ढे हों गए हैं। केन्द्र सरकार जो भी धनराशि का आवंटन इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए करती हैं, उसका सही इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। कमाबेश यही स्थिति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भी हैं। केन्द्र सरकार का यह लक्ष्य है कि वर्ष 2009तक देश की एह हजार की आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार की गंभीर स्थिति बिहार की सड़कों की हैं, उसे देखते हुए इस काम को करने के लिए भागीरथ प्रयास की आवश्यकता हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी नितांत अभाव हैं। जो भी स्वास्थ्य केन्द्र और सरकारी अस्पताल हैं, उनमें कोई भी सुविधा सही तरीके से उपलब्ध नहीं हैं। मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में बिहार को प्रमुखता प्रदान की जाए, ताकि समस्त आधारभूत ढांचे को सही स्वरूप में ढाला जा सके और इन सुविधाओं से वंचित लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।